भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

दिनांक 25–26 जून 2007
संसदीय सौध,
नई दिल्ली–110 001

कृषि संकट पर प्रस्ताव

आज भारतीय कृषि के सामने अन्दर और बाहर दोनों तरह से बहुआयामी चुनौतियां खड़ी हैं। कृषि संकट फैलता जा रहा है और किसान का ऋण बोझ बढ़ता चला जा रहा है जिसके कारण पूरे देश के सामने खाद्य सुरक्षा की चुनौती गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। देश भर में किसानों में हताशा और गुस्सा भरा पड़ा है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि सरकार उन्हें मंझधार में छोड़ रही है। दुर्भाग्य से लगता है कि यूपीए सरकार इस स्थिति की गम्भीरता को या तो समझती नहीं है या फिर उसे देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। सरकार ने वर्ष 2006 को 'किसान–वर्ष' के रूप में घोषित किया है। परन्तु इस वर्ष में किसान ही सबसे अधिक दुर्दशा में है और आज तक भी उनकी दुर्गति जारी है। किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए तथाकथित पैकेज भी बेमानी साबित हुआ है।

अधिकांश कृषि उत्पादों की कीमतें थोड़ी बढ़ी है या स्थिर बनी हुई हैं, वहीं कृषि बीजों आदि की कीमतें दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। कृषि आय में आई गिरावट, उत्पादन की बढ़ती लागत, समय पर पर्याप्त कर्ज उपलब्ध न होने, लाभप्रद मूल्यों के अभाव एवं प्राकृतिक आपदाओं, बार–बार खराब फसलों के कारण ऋणभार बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से हजारों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। पिछले चुनावों में किसानों की समस्या को एक बड़ा मुद्दा बनाए जाने के बावजूद भी यूपीए ने ऐसे कोई सार्थक उपाए नहीं किए हैं जिससे कृषि उत्पादों के लाभप्रद मूल्य मिल सकें, सस्ती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध हो पाएं, समय पर पर्याप्त कर्ज मिल सके, उत्पादों की ऊंची कीमत मिले, सिंचाई की निश्चित सुविधा मिले, समुचित दरों पर बीज, कीटनाशक तथा उर्वरक उपलब्ध हो पाएं। किसानों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया है और केवल मुंहजबानी बातें की जा रही हैं।

एक तरफ, औद्योगिक विकास में बढ़ोतरी हुई है तो दूसरी तरफ कृषि–विकास लगभग ज्यों का त्यों है। दूसरे क्षेत्रों की 4 प्रतिशत की तुलना में किसानों की प्रति व्यक्ति आय में मामूली सी 0.28 प्रतिशत वृद्धि हुई है। देश के लिए यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है जबकि जनसंख्या का 60 प्रतिशत से अधिक भाग आज भी कृषि पर ही आश्रित है। यह देख कर भी दुख होता है कि यूपीए सरकार द्वारा तैयार किए गए 11वीं योजना के 'एप्रोच पेपर' में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के मसले पर पूरी तरह असफल रही है, जबकि इसकी तत्काल आवश्यकता है।

देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की इस चेतावनी पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि ''यदि तेजी से उपचारी उपाय

नहीं किए गए तो स्थिति तेजी से बिगड़ती जाएगी। पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र पूरी तरह से उजड़ने की दिशा में बढ़ता जा रहा है।" यह बात भी विशेष रूप से ध्यान देने की है कि प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री दोनों ही इस बात पर अफसोस तो बहुत कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र बदहाली की तरफ बढ़ता जा रहा है, परन्तु सुधारात्मक उपाए करने पर चुप्पी साध रखी है। सच तो यह है कि सरकार ने देश के प्रति गहरा अनिष्ट किया है।

यूपीए सरकार ने लगभग कृषि आय बीमा योजना को तिलांजलि दे दी है और उसने फसल बीमा योजना पर भी उतना ध्यान नहीं दिया है, जिसकी शुरुआत एनडीए सरकार ने की थी। उसने नदी जोड़ने वाली अत्यंत लोकप्रिय तथा उपयोगी योजना को भी ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। यहां तक कि एनडीए सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता पर रखी गई ग्रामीण गोदाम, कोल्ड स्टोरेज चेन, ड्रिप सिंचाई, बागबानी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ भी अब दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

भाजपा का मानना है कि सरकार और देश को इस स्थिति की गम्भीरता से समझने की तत्काल आवश्यकता है और जरूरत है कि इसे ठीक करने के लिए तात्कालिक उपाए किए जाएं। भाजपा की यह भी सम्मति है कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार की जाए।

कृषि सम्बन्धी बजट प्रावधान में भी काफी कुछ गिरावट आई है और कृषि आश्रित जनसंख्या के 68 प्रतिशत भाग को कुल बजट आवंटनों का 2 प्रतिशत से भी कम प्राप्त हो रहा है।

भाजपा सरकार की निष्क्रियता की भारी निंदा करती है कि उसने राष्ट्रीय किसान आयोग की रचनात्मक सिफारिशों पर भी काम नहीं किया है, जिसमें आयोग ने कृषि मोर्चे की विभिन्न चुनौतियों को सामने रखा था और सरकार ने इस बारे में सही प्रत्युत्तर तक नहीं दिया है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनैतिक इच्छा होनी चाहिए जिसकी तत्काल आवश्यकता है। किसान के हितों और कल्याण की रक्षा करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र–सम्पदा में किसानों का विशाल योगदान है, विशेष रूप से खाद्यान्नों, दालों, गन्ना आदि के उत्पादन में उन्हीं का तो योगदान है।

एनडीए के शासनकाल में खाद्य–भण्डार विपुल मात्रा में था। यूपीए की गलत नीतियों के कारण, जिसमें खाद्यान्न खरीदारी की निष्क्रियता तथा पर्याप्त समर्थन मूल्यों का अभाव शामिल है, हमारी खाद्यान्नों की अधिकता कमी में बदल कर रह गई और इस प्रकार देश को खाद्यान्न–आयात के दिन देखने पड़े हैं, जो दीर्घकाल में किसानों के हितों पर और आधारभूत घरेलू उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव डालेंगी।

50 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न का आयात करने का भारत सरकार का निर्णय कोई अच्छा सोचा–समझा निर्णय नहीं है, असामयिक है और इससे देश के गेहूं उत्पादक किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यूपीए सरकार के शासनकाल में प्रति वर्ष गेहूं की खरीददारी घटती चली जा रही है। वर्ष 2002 में 206 लाख मीटरिक टन से घटकर वर्ष 2006 में 92 लाख मीटरिक टन तक पहुंच गई है। किसान आयोग की सिफारिश थी कि भारत में प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते दामों, पोषाहार तथा संतुलित खाद्यान्न के आधार पर देश में ही पैदा होने वाली सुरक्षा

उपलब्ध होनी चाहिए। यह तभी सम्भव है जब किसान उत्पादन बढ़ा सकेंगे और वह तभी सम्भव होगा जब उन्हें अपने कृषि उपज का बढ़ा और लाभप्रद मूल्य मिलेगा।

भाजपा निम्न क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने और सुधार करने के उपाय करने पर जोर देना चाहती है :

1. किसान आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पहले इसका गहन अध्ययन किया जाए, वहीं इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों एवं अन्य जानकारों से भी सलाह ली जाए।

2. अनाज, दालों, तिलहन, बीजों, तथा अन्य खाद्यान्न मदों की उपज बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाई जाए।

3. उच्च प्राथमिकता देकर नदियों को परस्पर जोड़ने के उपाए किए जाए, राज्यों को अपने अन्दर और उनके बीच नदियों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

4. एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि आय बीमा योजना को तुरन्त कार्यान्वित किया जाए।

5. उच्च उपज वाले बीजों के अनुसंधान तथा विकास के लिए पर्याप्त धन निवेश करके कृषि पैदावार को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए। प्रमुख खाद्यान्नों की उपज को बढ़ाने के लिए तकनीक की तलाश की जाए। बेहतर आधारभूत ढांचे, अनुसंधान और विस्तार सेवा का विकास हो, जो कृषि उपज और उत्कृष्ट किस्म का प्रमुख साधन है। कृषि संबंधी बजट–आवंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की जरूरत है।

6. विविध प्रकार की फसलों के पैटर्न को अपनाएं, सिंचाई सुविधाएं और खाद्य प्रसंस्करण और केन्द्रीभूत कृषि व्यापार गतिविधियों के माध्यम से उपज के मूल्यों में वृद्धि हो।

7. कृषि में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हो क्योंकि जीडीपी का प्रतिशत 3 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत पर आ गया है। कृषि आधारभूत ढांचे में और अधिक सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाए ताकि किसानों को फसलों का और अधिक लाभप्रद मूल्य मिले तथा कृषि को अधिक कारगर बनाया जा सके।

8. बेहतर कृषि प्रबंधन एवं खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कृषि आर्थिक क्षेत्र शुरु किए जाएं।

9. सभी जमीनों को सिंचाई योग्य बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक धन खर्च कर सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जाए। जरूरत इस बात की भी है कि और अधिक सिंचाई संभावनाओं का सृजन हो, कार्य–प्रणाली की कमियों को सुधारा जाए और जल उपलब्धता के अनुसार फसल–पैटर्न में भी बदलाव लाया जाए।

10. गुजरात सरकार द्वारा शुरु की गई मृदा उर्वरता कार्ड कार्यक्रम (Soil Health Card Programme) को राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया जाए, जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों को आदेश दिया गया है कि वे प्रत्येक

खेत में जाएं और वहां की मृदा गुणवत्ता की जांच करें। इस कार्ड से किसानों को मृदा में सही किस्म के पोषक तत्त्व डालने में सहायता मिलती है और इस प्रकार वे बेकार खर्चों से बच जाते हैं।

11. बैंक की ब्याज दरों को 4 प्रतिशत तक लाया जाए और कृषि को बैंकों के कर्ज का 25 प्रतिशत ऋण देने के निर्देश दिए जाएं।

12. कृषि क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान 10 प्रतिशत स्तर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक लाकर कृषि में सकल पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए तत्काल उपाए करना आवश्यक है।

13. वैज्ञानिक कृषि सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने तथा धन–निवेश की तत्काल आवश्यकता है।

14. ऐसी रणनीति बनाई जाए कि सेज के लिए उर्वरक भूमि का आवंटन न हो और सेज में स्टेकहोल्डर्स के रूप में किसानों के लिए इसे बाध्यकारी बना दिया जाए।

15. खाद्यान्न आयात करने के निर्णय को तुरन्त वापस लिया जाए क्योंकि इससे किसानों के हितों को नुकसान होता है और इसकी बजाए देश के किसानों को ही उनकी उपज का उतना मूल्य दिया जाए जो विदेशी एजेंसियों को प्रस्तावित किया जाता है।

16. बागवानी, ड्रिप सिंचाई, खाद्यान्न, प्रसंस्करण, डेयरी, पॉलट्री, मत्स्य पालन के लिए और अधिक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जाए और दस वर्षों के लिए कर छूट की घोषणा कर दी जाए।

भाजपा, सरकार से अपनी मानसिकता बदलने का आह्वान करती है और चाहती है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सभी मुख्य मंत्रियों और राजनैतिक दलों की बैठक बुलाए ताकि कृषि मोर्चे पर सुधार किया जा सके एवं और अधिक सार्वजनिक निवेश तथा किसान–समर्थक नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया जाए।

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र केरल और कर्नाटक में भीषण बाढ़ से हुई तबाही में साढ़े तीन सौ लोगों की मृत्यु एवं फसल एवं सम्पति की भारी क्षति पर गहरा दुख व्यक्त करती है। भाजपा सरकार से यह आग्रह भी करती है कि सरकार प्रभावित राज्यों के लिए तदर्थ सहायता घाषित करे और प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए और उनके पुनर्वास की योजना बनाने के लिए एक केन्द्रीय टीम वहां भेजे।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी दीर्घ–अवधि के लिए कृषि के संरक्षण और किसानों के कल्याण हेतु एक व्यापक कृषि नीति तैयार करने के लिए समिति गठित करने का संकल्प करती है। यह समिति किसान आयोग की सिफारिशों का तथा साथ ही भूमि संबंधित मुद्दों का अध्ययन करेगी और इस संबंध में अपनी सिफारिशें पार्टी को प्रस्तुत करेगी।

******